THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) There are 8 telephone exchanges in Cooch-Behar District with 838 working connections and a waiting list of 28.

(b) and (c). About 30 new connections may be provided by March, 1981, 15 at Cooch-Behar and rest in other exchanges.

विस्थापित दुकानदारों का पुनर्वास

1907 श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन दुकानदारों के पुनर्वास की योजना तैयार की थी जिनकी दुकानें तथा स्टाल 1975 में दिल्ली तथा नई दिल्ली में सफाई अभियान के दौरान गिरा दिये गये थे, और जिन्हें उनके स्थान पर कोई स्टाल आवंटित नहीं किए गए थे जबकि 250 रु० जमा कराने पर उन्हें दुकान देने का प्रावधान था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों ने स्टाल के लिए आवेदन पत्र दिया और कितने व्यक्तियों को वास्तव मे स्टाल आवंटित किए गए ;

(ग) ऐसे लम्बित मामलों की संख्या कितनी है जिनमें स्टाल के लिए आवेदन-पत्र दिया गया था परन्तु वास्तव में दुकान का आवंटन किया गया था और आवेदक ने पुनः स्टाल की मांग की ; और

(घ) ऐसे मामले कब से लम्बित हैं और उन पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और ऐसे आवेदकों को स्टालों का आवंटन कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान के दौरान हटाये गए उन लोगों के लिए जिनको वैकल्पिक स्थल नहीं दिए गए थे, दुकान/स्टाल आवंटन करने के लिए 1977 में एक योजना घोषित की थी और उसके लिए निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे । प्रत्येक आवेदक को दुकान या स्टाल, जैसी भी स्थिति हो, के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रु० या 250/- रु० धरोहर राशि के रूप में जमा करना अपेक्षित था ।

(ख) स्टालों के आवंटन के लिए 71 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 6 व्यक्तियों को पात्र पाया गया । परन्तु चूंकि उस समय कोई स्टाल उपलब्ध नहीं था इस लिए उनको स्टाल के स्थान पर दुकान आवंटित की गई थी ।

(ग) तथा (घ). उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने दुकान के स्थान पर स्टाल आवंटन के लिए प्रतिवेदन दिया था । इस प्रयोजन के लिए उसका अनुरोध दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में 12-11-79 को प्राप्त हुआ था । इस मामले में स्टाल आवंटन के अनुरोध को लम्बित रखा गया क्योकि स्टाल उपलब्ध नहीं थे । अब कुछ स्टालों का निर्माण किया गया है और अब स्टाल के आवंटन के लिए आवेदक के अनुरोध पर भी शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

Relief to Fishing Industry

1908. SHRI DAULAT SINHJI JADEJA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether in view of the prevailing depression in fishing Industry, what relief Government propose to grant to fishing industry;

(b) since oil price has risen by 50 per cent recently whether Government have taken note of various representations made for relief; and

(c) if so, what are the details of relief or assistance since the oil price rise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) There is no depression in the fishing industry as a whole.

(b) Yes, Sir.

(c) The representations are being examined in consultation with the concerned Ministries.

Cross bar telephones and switching equipment and their manufacture

1909. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to a report in the *Times of India* dated September 22, 1980 that the Indian Telephone Industries and the Telecommunications Research Centre have completely re-designed cross-bar telephones, switching equipment for the manufacture of which foreign offers from Sweden, etc. have also come;

(b) if so, the facts in this regard and whether the idea of foreign collaboration has been given up; and

(c) how much of foreign exchange is likely to be saved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) and (b). The attention of the Government has been drawn to the report in the *Times of India* dated September 22, 1980. The Indian Crossbar Project Group, consisting of representatives from Indian Telephone Industries and Telecommunications Research Centre of P&T Department was set up for the development of an indigenous crossbar telephone system by extensive re-designing of the imported Pentaconta system, to make it suitable for Indian conditions. Messrs. L. M. Ericsson of Sweden and two Japanese firms had submitted tenders and Messrs. Indian Telephone Industries Ltd. of Bangalore had submitted a proposal for setting up the proposed crossbar switching equipment factory at Rae Bareli. The Government have, after careful consideration of the foreign tenders and the proposal of ITI Ltd., decided in favour of adopting the Indian Crossbar Project system offered by Indian Telephone Industries Ltd., for manufacture at Rae Bareli factory. For this purpose, ITI Ltd. will have a limited collaboration with Messrs. BTM Ltd. of Belgium. But no payment will have to be made for transfer of knowhow.

(c) The annual foreign exchange saving by adopting the indigenously developed Indian Crossbar Project System is estimated to range from Rs. 5.6 crores to Rs. 7.3 crores per year after reaching full production.

Telephone Advisory Committee in Punjab

1910 SHRI L. S. TUR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Telephone Advisory Committees have been constituted;

(b) if not, when these will be constituted;

(c) whether due representation will be given to all political parties; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) No Telephone Advisory Committee of Punjab has so far been formed.